डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/ म.प्र./ मन्दसौर/ 122/ 2024- 26
ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अख़बार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 19 | अंक 258 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | शुक्रवार 04 जुलाई 2025 | मूल्य 2 रुपया

पचहत्तर ग्राम एमडी के साथ मिला डोडाचूरा, बाईक सवार दो युवक गिरफ्तार

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। अफजलपुर पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ बाईक सवार दो युवको को पकड़ा है। इनके कब्जे से डोडाचूरा भी मिला है। मामले में एक आरोपी की तलाश की जा रही है।

अफजलपुर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर असावती कुचड़ोद आम रोड चेक पोस्ट अर्निया गुर्जर पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक बिना नम्बर की बाईक एचएफ डीलक्स को रोका गया। इनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 75 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और 05 किलो 900 ग्राम डोडाचूरा मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम गफ्फार पिता मोहम्मद खान निवासी मुण्डलाराम थाना कालुखेडा जिला रतलाम और फारुख पिता लियाकत खान निवासी मुण्डलाराम थाना कालुखेडा जिला रतलाम बताया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ अरविन्द सिंह चन्द्रावत निवासी लसुड़िया नाथी थाना कालुखेडा जिला रतलाम से लाये है। पुलिस ने अरविंद को भी आरोपी बनाया है। बता दें कि तीनो आरोपियो के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियो को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

सामने आ रही रिछा चांदा की कहानी...

सूत्रो की माने तो एक पंडित के जरिये पाटी बनकर पहुंचे थे। आरोपियो को कथित रूप से जयपुर की पार्टी से मिलाने के बहाने बुलाया गया था। रिछा चांदा से बुधवार शाम करीब 05 बजे तीन लोगो को उठाकर लाने की खबर थी। हालांकि, लिखापढ़ी में समय लगता है। इसलिये देर रात कायमी की गई होगी। इधर एक को हाथो-हाथ विदा करने की कहानी भी चर्चा में है। यदि सूत्र की बात सही है तो अपनी नीर-क्षीर कार्यशैली के लिए ख्यात पुलिस कप्तान को सही जांच कराना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि अफजलपुर से पहले कई कारणो से हटाये गए आरक्षक और हेडसाब को पुनः वहीं पदस्थ करना कहीं गले की हड्डी ना बन जाये?

सरकार...समोसा ही मंदसौर में 25 रुपए का है..!

20 रुपए रोज देकर उड़ा रहे दिव्यांगों का मजाक ?

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। लाडली बहना की राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 1250 रूपए की गई है। भाईदूज और राखी सहित अन्य त्योहारों पर लाडली बहना हो या किसान अथवा अन्य वर्ग, सरकार विशेष ध्यान रख रही है। लेकिन, उपेक्षा कहे या उपहास, दिव्यांग इसका शिकार बन रहा है। मामला है दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन का। जो सरकार 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से छह सौ रुपए महिना दे रही है। जबकि, मंदसौर में 25 रुपए का तो सिर्फ समोसा ही मिल रहा है। ऐसे में 600 रुपए प्रतिमाह में दिव्यांग की कौन सी जरुरत पूरी होगी, यह तो सरकार ही जाने? जबकि, सरकार ने 1500 रुपए पेंशन का वादा किया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्ष 2016 में विकलांग शब्द को बदलकर दिव्यांग किया गया था। लेकिन, जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न तो पेंशन राशि में वृद्धि हुई है और न ही सुविधाओं में।

16 साल में बढ़ाए सिर्फ 300 रुपए...

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना 01 अप्रैल 2009 में शुरु की गई। शुरुआत में इसमें तीन सौ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। जिसमें सौ रुपए राज्य सरकार और दो सौ रुपए केंद्र सरकार देती थी। इसके बाद 16 साल में महज 300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर राशि को 600 रुपए किया गया है। जबकि 16 साल पहले में के हिसाब से वर्तमान में महंगाई सातवें आसमान को भी पार कर चुकी है।

चाय-नाश्ता तक नहीं आ रहा 20 रुपए रोज में...

छह सौ रुपए प्रतिमाह दिव्यांगों को दिया जा रहा है। मतलब 20 रुपए रोज उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। बीस रुपए रोज में तो मंदसौर में चाय-नाश्ता तक नहीं आ रहा। समोसे की कीमत मंदसौर में न्यूनतम 15 रुपए से 25 रुपए तक पहुंच चुकी है। वहीं चाय दस रुपए की मिल रही है। मतलब चाय-नाश्ता 35 रुपए में मिल रहा है। अब इस पेंशन से रोटी और कपड़ा की आवश्यता पूरी हो पाना तो नामुनकीन है।

हाईकोर्ट का आदेश, सरकार का वादा...

हाईकोर्टने सरकार को नियमों के अनुसार दिव्यांग पेंशन देने का आदेश दे चुका है। सत्ताधारी भाजपा ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगों को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। लेकिन, इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है।

क्या कहता है कानून दिव्यांगजन...

अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 (1) केमुताबिक, प्रदेश में किसी भी योजना में दी जाने वाली सर्वाधिक राशि से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक राशि दिव्यांगों को देना होती है। यह नियम दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए थे।

अन्य राज्यों में सरकार ने बढ़ाए रुपए...

आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां छह हजार रुपए, हरियाणा में तीन हजार रुपए, तेंलगाना में 1500 रुपए, बिहार में 1100 रुपए, दिल्ली में ढाई हजार रुपए, गोवा में दो हजार रुपए प्रतिमाह दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है। जबकि, सबसे कम आंकड़ा मप्र सरकार का ही है। इसमें केंद्र का हिस्सा वही है जो सभी जगह दिया जाता है। राज्य सरकारों ने अपना हिस्सा बढ़ाकर पेंशन राशि बढ़ाई है। जबकि, कुछ ही समय पहले शुरु हुई लाडली बहना योजना में पद्रह सौ रुपए दिवाली से मिलने लगेंगे। वहीं 2028 तक राशि को तीन हजार करने की घोषणा भी सीएम कर चुके हैं।

कुएं में मिली डोडाचूरा से भरी कार, पुलिस जांच में जुटी

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नावनखेड़ी में बिना मुंडेर के कुएं से डोडाचूरा से भरी क्रेटा कार मिली है। जिसमें से एक दर्जन कट्टों में भरा डोडाचूरा मिला है। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची। मामले में जांच की जा रही है।

गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने कुएं में एक वाहन गिरा देखा, जिसके बाद आसपास जमा हुई भीड़ ने उसमें रखे कट्टों को भी देखा। शंका होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नाहरगढ़ थाना प्रभारी प्रभात गौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से कुएं से कार को बाहर निकाला गया। कार की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि उसमें डोडाचूरा से भरे लगभग 12 कट्टे रखे हुए थे। पुलिस के अनुसार घटना स्थल पर कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वाहन में नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे पहचान में भी परेशानी हो रही है। शुरूआती जांच में आशंका है कि किसी अवैध मादक पदार्थों के तस्कर द्वारा पीछा छुड़ाने के लिए कार को कुएं में धकेला गया हो या फिर वाहन खुद असंतुलित होकर गिरा हो।

फिलहाल प्रकरण दर्ज नहीं...

टीआई प्रभात गौड़ ने बताया कि कार के अंदर डोडाचूरा भरा हुआ मिला है। लेकिन, फिलहाल कोई आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है, इसलिए अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। प्रथम दृष्ट्या यह अवैध मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा मामला प्रतीत हो रहा है।

क्षेत्र में फैली सनसनी...

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिना मुण्डेर के कुएं कई जगह खुले पड़े हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। वहीं, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार और डोडाचूरा की जब्ती की पूरी प्रक्रिया में लगी है और वाहन के मालिक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नावन खेड़ी मामला: पुलिस की फील्डिंग थी या हादसा हुआ? मजिस्ट्रीयल जांच हो

राजू सोनी

नाहरगढ़ 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नावन खेड़ी मामला पूरे क्षेत्र में जमकर चौपाल पर चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। यह हादसा है या नाहरगढ़ पुलिस की फील्डिंग इसके पीछे मुख्य कारण है, इसकी मजिस्ट्रीयल जांच होना चाहिए, यह बात पूरे क्षेत्र में चौपाल की चर्चा का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। नाहरगढ़ पुलिस को हुआ क्या हैं? इनको सुंदरकांड का पाठ या शनि देव की पूजा करना चाहिए। क्योंकि, जिस काम में हाथ डालते हैं, उसमें जबरदस्त तरीके से बदनामी हासिल होती हैं। जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा हैं।

गाड़ी का हादसा हुआ या करवाया गया..?–मामले में यह चर्चा भी चल रही हैं की यह हादसा हुआ हैं या नाहरगढ़ पुलिस जवाबदार है? इसका कारण यह माना जा रहा हैं कि पुलिस लंबे समय से ऐसी ही कारगुजारी करती रहती हैं। शायद लगता है कि थाना पुलिस को किसी राजनीति या बड़े अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा...? यह डोडाचुरा के इतने प्यासे हो गए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। आगे की निष्पक्ष जांच समस्त जनता चाहती है.?

पूरे घटनाक्रम की हो मजिस्ट्रीयल जांच–पुलिस ने जो क्रेटा कार पकडी थी, उसमें सूत्र बताते है कि गरोठ क्षेत्र से छिलका लाना बताया जा रहा है? इस पूरे मामले को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में जो नावन खेड़ी का मामला हुआ हैं। इसमें कुछ तस्वीर अलग नजर आ रही हैं। इसकी जांच होना अति आवश्यक हैं। जिससे जनता के मन में विश्वास की अलख जग सके.. जिले के अधिकारियो को संपूर्ण जांच कराना चाहिए।

जनता का अनुमान कार के पीछे नाहरगढ़ पुलिस थी...?–इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र की चौपाल पर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। पर हकीकत नाहरगढ़ पुलिस ही जानती है। क्या नाहरगढ़ पुलिस के पीछा करने से यह हादसा हुआ...? या मौका स्थिति पर पीछे लगे हुए थे...? जिससे गाड़ी बिना मुंडेर कुए में जा गिरी...? इस पूरे मामले की सचाई जनता जानती हैं कि माजरा क्या हैं.? पर पुलिस के उच्च अधिकारी स्वयं जांच कराये तो सचाई सामने आ सकती हैं। जिससे सरकार की छवि खराब होने से बच सकेगी। बीजेपी संगठन को भी जिले में चल रहे ऐसे कार्यो की तरफ अपनी पैनी नजर घुमाते हुए पुलिस विभाग की अवैध गतिविधिया अगर चल रही हैं तो रोकना चाहिये।

कार की टक्कर से मंडी व्यापारी की मौत

कलेक्टोरेट रोड पर हुआ हादसा

डॉक्टर की कार ने खड़े वाहन को टक्कर मारी

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शहर के कलेक्टरेट मार्ग पर गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में युवा मंडी व्यापारी दीपक जैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दीपक जैन तहसील कार्यालय से निकलने के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को साइड में खड़ा कर मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शाम करीब सवा चार बजे का है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कई फीट दूर जाकर गिरा, वहीं दीपक जैन को गंभीर चोटें आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड दिया। कार की गति इतनी तेज थी कि डिवाडइर से टकराकर कार पलटकर नाले में उतर गई। कार निजी अस्पताल में कार्यरत सर्जन डॉक्टर अश्विन पंड्या चला रहे थे। मृतक दीपक पिता पारसमल जैन मंदसौर मंडी में मारुति फूड के संचालक थे तथा दशरथ आयल मिल के मालिक दशरथ जैन के भतीजे थे। दीपक की मृत्यु की खबर सुनकर व्यापार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल दीपक को तत्काल सिद्धि विनायक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मंडी व्यापारी और परिचित बडी संख्या में अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद पुलिस ने चार पहिया वाहन को कब्जे में लिया और मामलें की जांच शुरु की हैं। दीपक की शवयात्रा शुक्रवार सुबह 9 बजे निवास स्थान से शव वाहन द्वारा मंदसौर मुक्तिधाम जाएगी।

पिपलिया मंडी में जीएसटी टीम की कार्रवाई, लोहा व्यापारी के यहां टैक्स चोरी की जांच

उज्जैन से आई टीम ने श्रीनाथ ट्रेडर्स पर की छापामार कार्रवाई

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। पिपलिया मंडी नगर के बायपास स्थित श्रीनाथ ट्रेडर्स फर्म पर जीएसटी विभाग की टीम ने गुरुवार शाम टैक्स चोरी की सूचना पर छापा मारा। उज्जैन से आई करीब पांच अधिकारियों की टीम ने फर्म संचालक उमेश फरक्या के यहां दस्तावेजों की जांच की।

विभाग को इस फर्म पर लंबे समय से व्यापार में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। व्यापारी लोहे के सलिये व अन्य उपकरणों का बड़े पैमाने पर विक्रय करता है। देर रात तक कार्रवाई जारी रही, हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

कनघट्टी में चल रहा था अवैध दवाखाना, प्रकरण दर्ज

पिपलिया मंडी, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रहे दवाखाना संचालक के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार बस स्टेण्ड के पास कनघट्टी में संचालित गुरुकृपा बंगाली दवाखाना का ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर मल्हारगढ़ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रुप से दवाखाना संचालित पाया गया। बीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने गुरुकृपा बंगाली दवाखाना के संचालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया।

देर रात से सुबह तक झमाझम, दोपहर में धूप

नीमच में गांवों से संपर्क टूटा, ब्राह्मणी नदी खतरे के निशान से ऊपर

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। अंचल में मौसम रोज अलग-अलग रंग दिखा रहा है। बुधवार देर रात से लेकर सुबह तक रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। गुरुवार को भी सुबह 11 बजे तक बारिश का दौर चला। जिसके बाद दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर बाद धूप खिल गई। इसके बाद शाम को फिर बादलों का डेरा आसमान पर दिखाई देने लगा।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार दोपहर तक मंदसौर में 12 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं 05 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर नीमच में भयंकर बारिश का दौर जारी है। यहां कई गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है तो ब्राहमणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है।

नीमच जिले में 18 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले में अब तक 10 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। जबकि, बुधवार शाम तक 24 घंटों में करीब 02 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण नदी-नालों में उफान आ गया है। 08 घंटे तक नीमच-कोटा राजमार्ग पूरी तरह से बंद रहा। ताल और उमर गांव की नदी की पुलिया पर पानी भर जाने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। सिंगोली तहसील के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। जाट क्षेत्र की लोटन नदी की पुलिया पर तेज बहाव के कारण राजस्थान के कनेरा, विजयपुर और बेगू से नीमच का संपर्क भी टूट गया। कई स्थानों पर लोगों को बहते पानी में से वाहन निकालते देखा गया। उमर गांव में तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल और रतनगढ़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सिंगोली नगर की प्रमुख ब्राह्मणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर की चारों दिशाओं से आने-जाने वाले रास्ते जलभराव के कारण बंद हैं। रतनगढ़ क्षेत्र की गुंजाली नदी भी उफान पर रही।

खेत में सो रहे किसान की हत्या

गरोठ, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। थाना क्षेत्र के कछालिया गांव में बुधवार की रात खेत में सो रहे 62 वर्षीय किसान बालाराम गायरी की हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह मिले शव पर चोट के कई निशान हैं। उनका एक पाव पूरी तरह से कट गया है। सिर पर भी चोट के गहरे निशान हैं। सूचना मिलते ही गरोठ थाने से उप निरीक्षक मांगीलाल चौहान मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी हरीश मालवीय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरील ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया गया है कि मृतक के दो बेटे राजू और मांगीलाल हैं। उनकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। घटना के बाद से बेटा राजू फरार है। इस कारण पुलिस को उस पर संदेह है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गरोठ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां पीएम के बाद शव परिजनो के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी।

चीतों को भाया गांधीसागर अभ्यारण्य, दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे चार और चीते

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। देश में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों में से दो प्रभास व पावक को गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ा गया है। दोनों चीते यहां की आबोहवा में रम चुके हैं। गर्मी और लू के मौसम में भी चीते सामान्य व्यवहार करते दिखे। ढाई माह में दोनों चीतों ने 30 से अधिक शिकार किए। अभयारण्य के अधिकारियों के अनुसार चीते औसत हर तीसरे दिन नीलगाय या अन्य शिकार को पकड़ रहे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य और अनुकूलन की स्थिति मजबूत दिख रही है।

ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से लाई जाने वाली चीतों की तीसरी खेप में से चार चीतों को यहां छोड़े जाने की तैयारी है। शेष चीते गुजरात भेजे जाएंगे। तीसरे चरण में कुल कितने चीते आएंगे, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

दो चरणों में लाए गए 20 चीते...

बता दें की दक्षिण अफ्रीका से दो चरणों में अभी तक 20 चीते लाए जा चुके हैं। पहले चरण में 08 और दूसरे चरण में 12 चीते लाए गए थे। जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। गांधीसागर अभयारण्य को भी चीतों का रहवास बनाने के लिए चुना गया है। कूनो से यहां लाकर छोड़े गए दोनों चीतों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहां का वातावरण उनके अनुकूल है। दोनों चीतों को 16.4 वर्ग किमी के बाड़े में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाए जाने के क्रम में केंद्रीय वनाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा है। अधिकारियों ने बताया कि गांधीसागर अभयारण्य में चार चीते अगस्त के अंत या सितंबर तक लाए जा सकते हैं।

इनका कहना–मानसून सीजन के बाद अफ्रीका से चार चीते यहां लाए जा सकते हैं। अभी वन विभाग का दल अफ्रीका का दौरा कर लौटा है। इसमें मप्र के सीसीएफ भी गए थे। चार चीते मप्र को मिलने पर सहमति बनी है।

संजय रायखेरे
डीएफओ मंदसौर

विचार-मंथन

संस्थानों के ढीले-ढाले रवैए के चलते होती है रैगिंग!

शैक्षणिक संस्थानों में नए सत्र के विद्यार्थियों से पुराने छात्रों के परिचय की परंपरा पुरानी है, पर पिछले कुछ वर्षों से यह प्रताड़ना का पर्याय बनती गई है। इस नई परंपरा को रैगिंग कहा जाता है। कई संस्थानों में तो यह इस हद तक क्रूर देखी-पाई गई है कि कई नए विद्यार्थियों ने तंग आकर जान तक दे दी। इसे रोकने के लिए कड़े नियम-कायदे बनाए गए, इसके दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाते हैं, जेल तक भेजने का प्रावधान है, उन्हें संस्थान से निलंबित कर दिया जाता है। फिर भी हैरानी की बात है कि परिचय की यह भयावह परिपाटी बंद नहीं हुई है। विचित्र बात है कि इसे रोकने में देश के कई बड़े शैक्षणिक संस्थान भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने चिह्नित किया है कि कई संस्थान रैगिंगरोधी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते और न उन्होंने इसके व्यावहारिक उपाय कर रखे हैं। इसे लेकर यूजीसी ने चार आइआइटी, तीन आइआइएम सहित देश भर के नवासी शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इनमें सत्रह राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान हैं। यूजीसी ने कहा है कि अगर इन संस्थानों ने तीस दिन के भीतर रैगिंगरोधी मानदंडों का अनुपालन नहीं किया तो उनकी वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी, उनकी मान्यता रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। दरअसल, रैगिंग की वजह से विद्यार्थियों के मन-मस्तिष्क को पहुंचने वाले आघात के मद्देनजर यूजीसी विनियमन के तहत नियम

बनाया गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान दाखिले के समय सभी विद्यार्थियों और उनके माता-पिता से रैगिंग में हिस्सा न लेने का शपथपत्र और हलफनामा जमा कराएंगे। मगर यूजीसी ने जांच में पाया है कि इस नियम को बने करीब पंद्रह वर्ष बीत जाने के बावजूद सभी संस्थान इसका ठीक से अनुपालन नहीं करते। यही नहीं, रैगिंग पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए उनमें समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई है। समझना मुश्किल नहीं है कि संस्थानों के इस ढीले-ढाले रवैए के चलते विद्यार्थियों में रैगिंग करने का साहस बनता है। यों तो हर संस्थान में बड़ी-बड़ी पट्टिकाएं लगा कर घोषित किया जाता है कि उनके परिसर में रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, पर हकीकत यह है कि उनमें रैगिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। उन पर ध्यान तब जाता है, जब कोई बड़ी घटना घट जाती है। सवाल है कि किसी संस्थान को रैगिंग जैसी क्रूर परंपरा को बंद कराने में ढिलाई क्यों बरतनी चाहिए।पुराने विद्यार्थियों का नए विद्यार्थियों से परिचय, मेलजोल कोई बुरी बात नहीं है। मगर इसके नाम पर किसी का मजाक उड़ाना, उसे प्रताड़ित करना, इस कदर भयभीत कर देना या उसमें हीन भावना भर देना कि वह मानसिक त्रास से अवसाद में चला जाए या खुदकुशी जैसा कदम उठा ले, तो इसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। पुरानी परिपाटी तो नए विद्यार्थियों के स्वागत समारोह की रही है, उसने रैगिंग का विकृत रूप कैसे ले लिया, कहना मुश्किल है। मगर कोई शैक्षणिक संस्थान खुद इस विकृत रूप को कैसे बने रहने दे सकता है। क्या उन संस्थानों को इस बात की जानकारी नहीं कि रैगिंग के दौरान क्या होता है और उसका नए विद्यार्थियों पर कैसा असर पड़ता है। फिर दाखिले के वक्त उनसे यह शपथ-पत्र लेने में क्यों गुरेज होनी चाहिए कि वे रैगिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से बेचैन हुआ विपक्ष

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन –एस.आई.आर.) का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसकी इस पहल का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और वास्तविक बनाना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ के व्यापक आरोप लगाए हैं। लगभग सभी ने एसआईआर का विरोध किया है और कहा है कि इससे मताधिकार से वंचित होने का गंभीर खतरा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 7.89 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इस तरह का आखिरी गहन संशोधन 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची को फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें 4.96 करोड़ लोगों के नाम हैं। इनमें शामिल लोगों को जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे। बाकी 3 करोड़ मतदाताओं को प्रमाण के लिए दस्तावेज देने होंगे। वोटिंग लिस्ट में ये संशोधन ऐसे वक्त किए जाने हैं जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराजगी जता रही हैं। इस मसले पर विपक्ष की ओर से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दे उठाए थे और व्यावहारिक समस्याएं बताई थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 जून को महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग के बारे में कई बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, ज्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर

वहां भी, जहां-जहां बीजेपी हार रही होगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने 28 जून को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पिछले दरवाजे से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लाने का एक भयावह कदम है। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने 27 जून को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। जबकि सत्तारूढ़ दलों ने इसे पूर्व की चुनावी धांधली पर चुनाव आयोग की सख्ती के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2003 में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था तो उसमें दो साल लगे थे और तब साढ़े चार करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का मानना है कि विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले सघन पुनरीक्षण अभियान संभव नहीं है। राजद नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की इतनी आवश्यकता है, तो यह केवल बिहार में ही क्यों किया जा रहा है? क्या देश के अन्य राज्यों को इसकी जरूरत नहीं है? नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया बिहार को निशाना बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है। संविधान का अनुच्छेद 324 (1) भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के- चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग बिहार के बाद, चुनाव आयोग इस वर्ष के अंत तक 2026 में चुनाव होने वाले पांच राज्यों में मतदाता सूचियों की इसी प्रकार की समीक्षा करेगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मई-जून में समाप्त हो रहा है। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों की बड़ी संख्या है। राजनीतिक हलकों में इस बात की जोरों से चर्चा है कि बिहार के बाद मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बारी पश्चिम बंगाल की होगी। तभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। तृणमूल कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट करके मतदाताओं के नाम काटे तो उसका फायदा भाजपा को होगा। पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जिसके बारे में भाजपा आरोप लगाती है कि इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या की है। इनका वोट एकमुश्त तृणमूल को जाता है। हर क्षेत्र में 10 से 20 हजार नाम अगर कट जाते हैं तो तृणमूल को उसका बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बिहार से उलट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। वे आसानी से नाम नहीं कटने देंगे। पिछले कई महीनों से वे खुद घर घर जाकर सब चेक कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वालों के अनुसार, निर्वाचन आयोग देश में अवैध रूप से बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आकर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है। वैसे लोगों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी अवैध रूप से बिहार आकर बस गए हैं, उनका वोट विपक्ष को जाता है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हो या ओवैसी, इनको इस बात का डर सता रहा है कि मतदाता सूची से यदि इनका नाम कट गया तो उनका राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। बिहार के सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी 40 फीसदी से 70 फीसदी तक हो चुकी है। यही कारण है कि वर्षों से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोक की मांग उठती रही है। कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की भी खबर उठी थी। केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी तो बिहार में इस इलाके से भी विरोध के सुर उठे थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का वोट शेयर बढ़ा था। राजद को 23.11 फीसदी वोट मिले। भाजपा को 19.46 प्रतिशत ही वोट मिले, जदयू के खाते में 15.42 प्रतिशत वोट आया। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा और जेडीयू ने 12-12 सीटें जीतीं। आरजेडी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 सीटें और एलजेपी (आर) ने 5 सीटें जीती हैं। सीपीआई (एमएल) ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि एचएएम और एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती है। जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 17.70 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं।

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक?

संजीव कुमार मिश्र

यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव महिला संवाद कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं। महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर जोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियां सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी

नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई जीविका ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया जीविका दीदी नाम आज एक पहचान बन चुका है। वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। महिला संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और जीविका दीदी की रसोई व जीविका दीदी हाट जैसी पहल शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर राइस मिलों की स्थापना, वेजिटेबल मार्ट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की मांगें भी मुखरता से उठी हैं। लाइब्रेरी और पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की मांग की गई है। सामाजिक सुधारों में शराबबंदी की तर्ज पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, और सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी, हेल्प डेस्क तथा प्रखंड स्तर पर महिला थाना बनाने की मांगें भी प्रमुखता से रखी गई हैं।

भारत की आर्थिक प्रगति में अब तो ईश्वर भी सहयोग कर रहा है

वर्तमान में भारत कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लगभग 42 देशों से प्रतिवर्ष आयात करता है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल खरीद का 46 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आयात करता है। कुछ दिनों पूर्व भारत में दो विशेष घटनाएं हुईं, परंतु देश के मीडिया में उनका पर्याप्त वर्णन होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। प्रथम, भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में कच्चे तेल के अपार भंडार होने का पता लगा है, कहा जा रहा है कि कच्चे तेल का यह भंडार इतनी भारी मात्रा में है कि भारत, कच्चे तेल सम्बंधी, न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा बल्कि कच्चे तेल का निर्यात करने की स्थिति में भी आ जाएगा। यदि भारत को कच्चे तेल की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो इसका प्रसंस्करण कर, डीजल एवं पेट्रोल के रूप में, पूरी दुनिया की खपत को पूरा करने की क्षमता को भी भारत विकसित कर सकता है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में पूर्व में ही स्थापित है। अतः कच्चे तेल के साथ साथ डीजल एवं पेट्रोल का भी भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। जैसा कि दावा किया जा रहा है, यदि यह दावा सच्चाई के धरातल पर खरा उतरता है तो आगे आने वाले समय में भारत का विश्व में पुनः 'सोने की चिड़िया' बनना लगभग तय है। भारत आज पूरे विश्व में कच्चे तेल का चीन एवं अमेरिका के बाद सबसे बड़ा आयातक देश है और विदेशी व्यापार के अंतर्गत भी कच्चे तेल के आयात पर ही सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। कच्चे तेल का उत्पादन यदि भारत में ही होने लगता है तो न केवल इसके आयात पर होने वाले भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के खर्च को बचाया जा सकेगा बल्कि पेट्रोल एवं डीजल के निर्यात से विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में अर्जन भी किया जा सकेगा। जिसके कारण, भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार में अतुलनीय बचत एवं संचय होता हुआ दिखाई देगा और इस प्रकार भारत विश्व में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा संचयक देश बन सकता है। वर्तमान में भारत कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लगभग 42 देशों से प्रतिवर्ष आयात करता है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल खरीद का 46 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आयात करता है। वर्तमान में भारत द्वारा कच्चे तेल एवं गैस के आयात पर 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि खर्च प्रतिवर्ष किया जा रहा है। भारत सरकार के पेट्रोलीयम मंत्री श्री हरदीपसिंह जी पुरी ने जानकारी प्रदान की है कि अंडमान एवं निकोबार के समुद्री क्षेत्र में कच्चे तेल एवं गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। एक अनुमान के अनुसार यह भंडार 12 अरब बैरल (2 लाख करोड़ लीटर) का हो सकता है जो हाल ही में गुयाना में मिले कच्चे तेल के भंडार जितना ही बड़ा है। गुयाना में 11.6 अरब बैरल कच्चे तेल एवं गैस के भंडार पाए गए हैं। इस भंडार के बाद गुयाना कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है जबकि अभी गुयाना का विश्व में 17वां स्थान है। वर्ष 1947 में प्राप्त हुई राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद के लगभग 70 वर्षों तक भारत की समुद्री सीमा की क्षमता का उपयोग करने का गम्भीर प्रयास किया ही नहीं गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्र में कच्चे तेल एवं गैस के भारी मात्रा में जो भंडार मिले हैं उनका अन्वेषण का कार्य समाप्त हो चुका है एवं अब ड्रिलिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। ड्रिलिंग का कार्य समाप्त होने के बाद कच्चे तेल एवं गैस के भंडारण का सही आंकलन पूर्ण कर लिया जाएगा।

आज का राशिफल

अब बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, प्रदेश में खुलेंगे विद्युत पुलिस थाने

भोपाल, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। अब मध्यप्रदेश में बिजली चोरी रोकना आसान होगा। गुजरात की तर्ज पर प्रदेश सरकार 'विद्युत पुलिस थानों' की शुरुआत करने जा रही है। इन थानों में प्रतिनियुक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जो बिजली विभाग की जांच टीमों के साथ जाकर औचक निरीक्षण करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा और केस डायरी तैयार करेगा।

पहले चरण में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में एक-एक विद्युत थाना खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। सीएम ने बिजली चोरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल की आसान उपलब्धता पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बकाया बिलों की समस्या खत्म हो सके। वहीं, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली पर 20% सस्ती दरों का लाभ मिलेगा। यह छूट पहले से उद्योगों को मिल रही थी, अब घरेलू उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 21 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि कुल 1.34 करोड़ मीटर लगाने का लक्ष्य है। इस कार्य की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और तेजी से कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटरिंग बिजली उपयोग में अनुशासन लाएगी और उपभोक्ताओं को फायदा भी होगा। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि पंपों को सोलर पंप में बदला जाए, ताकि बिजली लोड कम हो और आपूर्ति बेहतर हो। इसके साथ ही घने पेड़ों के नीचे से गुजरने वाली लाइनों पर कोटिंग कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि बारिश या आंधी के समय बिजली बाधित न हो। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि बकाया बिल वसूली के लिए समाधान योजना लाई जा रही है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट दी जाएगी। यह योजना 6 महीने के लिए लागू होगी। इसके बाद भी बिल न चुकाने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अगले दो साल में तीनों बिजली वितरण कंपनियों को लाभ में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट, सौर ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और राजस्व वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है।

श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार - कल्याण मण्डल सचिव ने बताया कि म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025-26 हेतु मंदसौर जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित/विधवा सहायता प्राप्त महिलाओं एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत श्रमिकों के नियमित अध्ययनरत (केवल दो बच्चों) को मण्डल से अध्ययन हेतु प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय से कार्यालयीन समय में 1 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक की अवधि में वितरित किये जावेंगे तथा उक्त अवधि में ही भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जावेंगे। समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण कर पालकगण 20 अगस्त 2025 तक मण्डल कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें। अंतिम दिनांक पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय परिसर में पौधरोपण

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। सांदीपनी महारानी लक्ष्मीबाई शास. कन्या उ.मा.वि. मंदसौर में इको क्लब द्वारा एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत संस्था के प्राचार्य के.सी. सोलंकी द्वारा छात्राओं के साथ मिलकर पौधरोपण किया गया। साथ ही इनरव्हील क्लब द्वारा भी विद्यालय परिसर में पौधे लगाए गए। संस्था के स्टॉफ में रेणुका आचार्य, जया सोनी, किरण परमार, मुनमुन जैन, मेघा वप्ता उपस्थित थे। प्राचार्य श्री सौलंकी ने पेड़ों के महत्व को बताते हुए कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिये जहां भी खाली जगह मिलती है वहां फलदार पौधे अवश्य लगाकर उसकी प्रति दिवस सुरक्षा कर समय-समय पर पानी देकर पेड़ बनावे तथा उसके बचाव के लिये हर संभव प्रयास करें। साथ ही यह भी कहा कि हमने 200 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया जिसे विद्यालय परिवार प्रतिदिन पूर्ण करने की और प्रयासरत है। इको क्लब प्रभारी श्रीमती जया सोनी ने कहा कि हमारे विद्यालय की बालिकाये एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है बालिकाये अपनी माता के साथ मिलकर घर पर या आसपास के परिसर में पौधे लगा रही है और पर्यावरण को हरा भरा रखने में योगदान दे रही है।

मनोकामना अभिषेक में अभिषेक शुल्क 500 के बजाय 100 रूपए किया जाना उचित-टांक

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। भगवान पशुपतिनाथ की महिला को राष्ट्रपति पहचान के लिये वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर श्री जी.के. सारस्वतजी ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को नवीन भव्य रूप देने की कल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से मनोकामना अभिषेक प्रारंभ किया था प्रारंभ में आर्थिक दृष्टि से अभिषेक में प्रयोग की गई सामग्री आदि के लिये दान की राशि का प्रावधान किया गया था।

कलेक्टर श्री सारस्वत के स्थानांतरण के बाद 2011 तक प्रबंध समिति स्वयं अभिषेक कराती रही। 2011 के बाद मनोकामना अभिषेक का दायित्व स्थानीय गायत्री परिवार ने लेकर लगातार 2012 से 2018 तक नि:शुल्क अभिषेक को जारी रखा और देखते-देखते 350 जोडों की क्षमता वाला सभागार (वर्तमान आराधना सभागार) अभिषेकार्थियों से जहां पूरा भर जाता था वहीं प्रति सोमवार सभागार के अतिरिक्त सभागार के नीचे दोनों परिसर भी पूरे भर जाते थे और तब एक नहीं तीन-तीन पारियों में अभिषेक होता था। अभिषेक में नगर ही नहीं आसपास क्षेत्रवासियों से ही नहीं म.प्र. और भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के दर्शनार्थी अभिषेक में सम्मिलित होते थे। वर्ष 2011 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान सपत्नीक पूरे समय मनोकामना अभिषेक में बैठे थे बाद में एक बार और अभिषेक के प्रारंभ से पूर्व मनोकामना अभिषेक मंच पर स्थानीय भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा की पूजा की थी। गायत्री परिवार के बाद मनोकामना अभिषेक प्रबंध समिति ने अपने हाथों में लेकर अभिषेक पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला बटुकों को सौंपा गया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रविन्द्र पाण्डेय ने अपने मन की पीडा बताते हुए कहा कि सम्पूर्ण श्रावण का हजारों अभिषेकार्थियों को समूह में एक साथ अभिषेकार्थियों का जो गरिमामय इतिहास रहा है वह धीरे-धीरे प्रबंध समिति की उदासीनता से सामाजिक संगठनों की बैठक कर उनको सहभागिता बनाकर उत्तरदायित्व नहीं सौंपते हुए और अभिषेक राशि में काफी वृद्धि करने से विगत 2 वर्षों से जब से प्रबंध समिति ने एकदम राशि 500 रू. कर दी है। उससे संख्या कम होकर गत वर्ष किसी दिन एक भी अभिषेकार्थी के नहीं बैठने से अभिषेक कराने वाले पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला के बटूकों को और प्रबंध समिति कार्यालयीन कर्मचारियों ने अभिषेक का क्रम परम्परा नहीं टूटे, मजबूरी में अभिषेक में बैठना पडा।

नगर में आम चर्चा है कि जब प्रतिमाह पशुपतिनाथ मंदिर दान पेटी से लाखों रुपये संग्रहित हो रहे है तो फिर सामग्री के लिये 500 रू. की रसीद काटने का क्या औचित्य है। राशि केवल 100 रू. होना चाहिये। प्रारंभ से लेकर गत वर्ष तक पूरे श्रावण मास प्रतिदिन अभिषेक में निस्वार्थ सहयोगी के रूप में सेवा देने वाले योग गुरु बंशीलाल टांक का कहना है कि श्रावण मास प्रारंभ होने से 2-3 सप्ताह पूर्व प्रबंध समिति द्वारा नगर के समस्त समाज के प्रमुखों की बैठक आयोजित की जाकर उनके सुझाव लिये जाकर और प्रतिदिन क्रमवार समाजजनों के अभिषेक करने से उपस्थिति बरकरार रहती थी परन्तु समाज प्रमुखों की बैठक आहूत नहीं करने से और राशि एकदम 500 रू. करने से अभिषेक अभिषेकार्थियों से नगण्य होता जा रहा है। गत माह प्रबंध समिति अध्यक्ष कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रावण मास पशुपतिनाथ कार्यक्रमों में मनोकामना अभिषेक को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने परन्तु समाज प्रमुखों की बैठक में नहीं बुलाने पर टांक ने जब इस संबंध में प्रबंधक श्री राहुल रूनवाल से चर्चा की तो उन्होंने गत माह के अंतिम सप्ताह में सभी समाज प्रमुखों की बैठक की कहा था परन्तु गत माह समाप्त हो गया। इस माह जुलाई का प्रथम सप्ताह भी आधा हो गया। श्रावण मास जो कि 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है जिसमें मात्र 8 दिन शेष रहे हैं परन्तु फिर भी अभी भी समय है प्रबंध समिति अध्यक्ष कलेक्टर श्रीमती गर्ग को तत्काल समाज प्रमुखों की बैठक आहूत करना चाहिये, जिससे मनोकामना अभिषेक का 15 वर्षों पुराना जो ऐतिहासिक गरिमापूर्ण गौरव गरिमा है वह खण्डित होकर टूटने नहीं पाये और अभिषेक की राशि 500 के स्थान पर 100 रू. करने पर कोई भी साधारण आम दर्शनार्थी भी लाभ ले सकेगा।

दीक्षारंभ समारोह कल

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर के प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे ने जानकारी देते हुऐं बताया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार महाविद्यालय में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षारंभ समारोह दिनांक 05 जुलाई 2025 को प्रात: 11.00 बजे श्री कुशाभाऊठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया जायेगा। प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि दीक्षारंभ समारोह में विभिन्न वक्ताओं द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एईडीपी पाठ्यक्रम, शासन की संचालित योजनाऐं, कॅरियर मार्गदर्शन योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेलकूद एवं युवा संसाधन व अन्य जानकारी प्रदान की जायेंगी। आपने नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करे।

एमपीपीए फार्मासिस्ट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन

जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने फार्मासिस्टों की एकजुटता पर दिया ज़ोर

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। MPPA फार्मासिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आज फार्मेसी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक का मुख्य रूप से संगठनात्मक मजबूती, नई कार्यकारिणी का गठन और फार्मासिस्टों की जमीनी समस्याओं पर विचार करना रहा।साथ ही नई सदस्यता अभियान प्रारंभ हेतु विचार विमर्श किया गया।बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी स्वीकारते हुए संगठन की मजबूती और फार्मासिस्ट हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया।

मध्यप्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं, लेकिन वर्षों र्से हम उपेक्षा के शिकार रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी एकजुटता का परिचय दें और अपने अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। संगठन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम संगठित रहें, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो हल न हो सके।हम सरकार से मांग करते हैं कि फार्मासिस्टों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। मिथुन वप्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर खाली पड़े फार्मासिस्ट के पदों पर अधिक से अधिक नियुक्ति हेतु सरकार से वार्तालाप करने हेतु संगठन प्रयास करेगा और जरूरत पड़ी तो चरणबद्ध आंदोलन भी करेगा।फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य सेवा में सम्मानजनक स्थान मिले ऐसे प्रयास संगठन करता रहेगा। नई जिला कार्यकारिणी को ज़मीन पर सक्रियता दिखानी होगी और जिले स्तर से लेकर शासन स्तर तक हर मंच पर फार्मासिस्टों की आवाज को मजबूती से उठाना होगा।फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी को लेकर भी रणनीति बनाई गई। सभी उपस्थित सदस्यों ने संगठन की एकजुटता और मजबूती के लिए एकमत होकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष मिथुन वप्ता ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमितसिंह ठाकुर एवं प्रदेश सचिव दीपक मिश्रा की सहमति कार्यकारिणी की घोषणा करी जिसमें जिला सचिव पद पर दीपक राठौर,सह सचिव पद पर हनीफ खान,जिला कोषाध्यक्ष पर रणजीत बसवा,जिला उपाध्यक्ष पर पर श्रीमती अनुराधा भार्गव,श्री विकास व्यास,श्रीमती हिमशिखा नंदवानी,श्री चंद्रशेखर शर्मा,श्री भारत पाटीदार बनाए गए।जिला प्रवक्ता पद पर संगठन के वरिष्ठ श्री जितेंद्र पांडे,जिला मीडिया प्रभारी श्री सतीश बैरागी,जिला संगठन मंत्री श्री लोकेश जैन के अलावा कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री पलाश झवर,पंकज चौधरी,आशीष जैन,सुनील पंचोली,राम बिरला,दिलीप प्रजापत,मयंक चुनेकर,प्रतीक तिवारी बनाए गए। संगठन के संरक्षक पद पर श्री नरेंद्र कुमार त्रिवेदी,श्री राहुल सोनी,श्री आशीष मंडलोई,श्री प्रीतेश राव,श्री पंकज सुराणा ,श्री डॉ कपिलेश दवे,श्री मुर्तजा अली बनाए गए एवं मार्गदर्शन मंडल हेतु श्री आशीष खिमेसरा,श्री पंकज सुराणा,श्री मनीष कुमावत,श्री प्रतापसिंह चंद्रावत,श्री शैलेंद्र चौधरी बनाए गए। उक्त जानकारी संगठन के प्रवक्ता जितेंद्र पांडे ने दी।

मारपीट करने वाली एक महिला सहित 05 आरोपियों को 03-03 माह सश्रम कारावास

नीमच, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद, जिला-नीमच द्वारा पुरानी रंजीश के कारण तीन महिलाओं सहित 04 व्यक्तियों से लट्ठ से मारपीट करने वाले एक महिला सहित 05 आरोपीगण (01) शैतानबाई उर्फ अमानबाई पति विरमचंद्र ऐरवाल, उम्र-48 वर्ष, (02) सीताराम पिता विरमचंद्र, उम्र-27 वर्ष, (03) ओमप्रकाश पिता विरमचंद्र, उम्र-23 वर्ष, (04) विरम पिता प्याराचंद्र्र, उम्र-50 वर्ष तथा (05) नारायण पिता विरमचन्द्र, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी-नई आबादी, ग्राम-झातंला, थाना-सिंगोली, जिला-नीमच को धारा 323/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना दिनांक 22 जून 2017 की सुबह के लगभग 09:30 बजे ग्राम झांतला स्थित फरियादीया के घर की हैं। फरियादिया शांतिबाई ने थाना सिंगोली में सूचना दी कि उसका व उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपीगण का पूर्व से विवाद होकर रंजीश चल रहीं हैं, जिस कारण घटना दिनांक को आरोपीगण ने एकमत होकर लट्ठ से उसके साथ, उसके दामाद राजू, उसकी लडकी हेमलता व सास सुंदरबाई के साथ मारपीट की थी। चिल्लाचोट की आवाज सुनकार की आवाज सुनकर रमेशचंद तथा गोपाल ने बीच-बचाव किया। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना सिंगोली में अपराध पंजीबद्ध किया गया व आहतगण का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया जाकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं चारों आहतगण को 1200-1200रू. प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।

रेडक्रास भवन नीमच में दिव्यांगजन शिविर 07 को

नीमच, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच द्वारा रेडक्रॉस सोसायटी नीमच में सोमवार 7 जुलाई 2025 को प्रात: 10:00 बजे से (ओडियो मीटरी) कान की जांच की जाएगी। जांच उपरांत दिव्यांग हितग्राही को श्रवण बाधित, मूकबधिर के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। जिस भी दिव्यांग हितग्राही को प्रमाण पत्र बनाना है, वह अपने साथ आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो 2, सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटोकापी के साथ शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 9713165344, 7694057218 पर संपर्क कर सकते हैं।

नवप्रवेशित छात्राओं को सौंपे पौधे

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर के प्राचार्य डा.सुधीर रायजादा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह के तृतीय दिवस में पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाते हुए महाविद्यालय की नव-प्रवेशित छात्राओं को पौधे सौंपे गये साथ ही अगले तीन वर्षों के उनके अध्ययनकाल में इनका रख-रखाव की जिम्मेदारी सौपीं। इस अवसर पर दीपिका सकुनिया, वंदना, अंजली आदि नव प्रवेशित छात्राओं व उनके अभिभावक श्री रामनिवासजी धनगर व श्री आशीषजी हिंदल द्वारा पौधारोपण किया गया। तीसरे दिवस के आयोजन में छात्राओं को शासन की हितग्राही योजनाओं की जानकारी दी गई। डा.कविता बुन्देला ने पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की जानकारी, डा.निरंजन गंगवाल ने सेन्ट्रल सेक्टर व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान की। गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, मुख्यमंत्री मेधावी एवं जनकल्याण योजना की जानकारी श्री कांतिलाल कुमावत द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठप्राध्यापक डा.पी.एल.पाटीदार ने प्रकृति का जीवन में महत्व बताते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प छात्राओं को दिलाया। कार्यक्रम का संयोजन डा.उमा गगरानी ने किया एवं आभार माना। इस आयेाजन में समस्त महाविद्यालयीन स्टाफ भी उपस्थित रहा।

साईबर धोखाधड़ी एवं डिजिटल साक्षरता का जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। सीतामऊके ग्राम खेजडीया में संस्था अरूणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति द्वारा आईशर फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल साईबर फाड विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉस्टर ट्रेनर आई. एच. मुन्सरी, वित्तीय साक्षरता द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं साइबर फाड विषय पर उपस्थित ग्रामीण जनो को विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि किस प्रकार साइबर ठग आपकी जमा पूंजी को विभिन्न आधुनिक तरीके से ठग सकते है। इसके लिये सर्तकता जरूरी है। डिजिटल सर्तकता रहेगी तो, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुचा पायेगा। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री अरविन्द सिंह राठौर, जनपद सदस्य, मन्दसौर एवं उपस्थित जन द्वारा मॉ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्ञवलन के साथ किया गया। संस्था के ट्रेनर श्री प्रवीण शर्मा द्वारा उपस्थित जनो को साईबर फ्रड व सोशल मिडिया प्लेटफार्म, ऑनलाईन पेमेन्ट, फर्जी वेबसाईट आदि के बारे में उदाहरण सहित रोचक जानकारी से अवगत कराकर सावधान रहने हेतु जानकारी दी गई। कार्यशाला में श्री सुरेन्द्र सिंह भदोरिया द्वारा वर्तमान समय में मोबाईल से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की सत्य घटनाओ से ग्रामीण जन को बताकर जागरूक रहने को कहा किसी भी प्रकार का ओटीपी या लिंक शेयर नहीं करना नही तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, सर्तकता ही बचाव है एवं डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानुन नहीं होता है। ऐसा कोई भी अधिकारी नही कर सकता है, जानकारी दी गई। संस्था के श्री भरत रामनानी द्वारा उपस्थित जनो का रजीस्ट्रेशन किया गया एवं सर्तकता किट दी गई, जिसमे साईबर जागरूकता पेम्पलेट, बजट डायरी, पेन दिये गये। संस्था के ट्रेनर श्री राजेश जोशी द्वारा साईबर जागरूकता के बारे में बताते हुए उपस्थित जनो से सवाल जवाब किए गए सही उत्तर देने वाले को इनाम भी दिया गया।

शौर्यादल योजनान्तर्गत मास्टर ट्रेनर्स का जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मंदसौर ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर मध्यप्रदेश के जिलों के ग्राम, वार्ड स्तर की आंगनवाडी क्षेत्र में शौर्यादलों का गठन किया गया। जिसमें आंगनवाडी क्षेत्र की 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बालिका/महिलांए सदस्य होती है।

सामुदायिक स्तर पर शौर्यादल एक महत्वपूर्ण ईकाई है, साथ ही यह दल किशोरियों की भागीदारी एवं उनके क्षमतावर्धन के लिए भी एक प्रभावी मंच है, इसको ध्यान में रखते हुए महिला बाल विकास विभाग मद्व-प्रद्व- के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला मंदसौर के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर शौर्यादल मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन 27 जुन एवं 28 जून 2025 को दो बेच में जनपद पंचायत मंदसौर के सभाहाल में किया गया। जिसमें जिले की समस्त 9 परियोजना से 45 चयनित, प्रत्येक परियोजना मे 5-5 बालिकाओं ने शौर्यादल के मास्टर ट्रेनर्म के रूप में भाग लिया एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनर्स को ममता फाउडेशन यूनिसेफ में जिले में पदस्थ जिला समन्वय श्री सौनिक मिश्रा, श्रीमती पूजा चौहान बाल संरक्षण अधिकारी महिला बाल एवं परियोजना अधिकारी श्री मनोज कुमार दुबे मंदसौर ग्रामीण 1 व बी.आर मुजाल्दे परियोजना अधिकारी मंदसौर शहर द्वारा विस्तार में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

चालीसा महोत्सव के समापन पर झूमे श्रद्धालू

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। सिन्धी हिन्दू समाज कि प्रमुख धर्मपीठ श्री प्रेम प्रकाश पंथ के संस्थापक व सनातन धर्म के प्रवर्तक मंगल मूर्ति आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊॅंराम महराज के 139 वे जन्मोत्सव एवं चालीसा महोत्सव का समापन समारोह श्री प्रेमप्रकाश आश्रम में संत श्री शम्भूलालजी के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ संगत ने झूम कर नृत्य कर मनाया गया। वहीं 139 दीपक प्रज्वलित कर भगवान लक्ष्मी नारायण एवं आचार्य टेऊंराम महाराज की महाआरती की गई व केक प्रसाद का भोग अर्पित किया गया।

इस आशय कि जानकारी श्री प्रेम प्रकाश सेवा मण्डली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शिवानी ने देते हुए बताया कि संत शम्भूलालजी ने अपने भजन- स्वामी टेऊॅंराम तुहि जे दर्शन सा मिठो, ज्ञान मिले भक्ति मिले ज्ञान मिले शक्ति मिले। इस भजन के माध्यम से संत श्री ने अपने मुखारविंद से कहा कि इस कलयुग में आपके सगे सम्बंधी के खून (रक्त) के रिश्ते से भी सतगुरु का रिश्ता बहुत बड़ा व श्रेठ हैं, इसलिए आपका हमारा स्वामी टेऊॅंराम महराज से दिल व खून का रिश्ता बन गया है, इसलिए आज 139 वर्ष बाद भी आचार्य श्री का जन्मदिन हम और आप लगातार 40 दिन तक मना रहे हैं। कोई भी प्राणी जन्म से महान् नहीं होता बल्कि कर्म से महान होता है। टेऊॅंराम महाराज की भी गुरु भक्ति व अच्छे कर्मों र्की कमाई हुई हैं इसलिए आज देश विदेश में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आपने अपनी वाणी को स्पष्ट करते हुए कहां की रावण, कुम्भकर्ण व विभिषण आपस में संगे भाई होकर ब्राम्हण कूल में जन्मे थे किन्तु इन तीनों में विभिषण भगवान श्री राम की शरण में आने से उनके कर्म सुधर गये व विभिषण पूजनीय हो गये। उसी प्रकार आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊॅंराम जी महाराज भी अपने सतकर्मों र्की कमाई के कारण पूजनीय हो गये। इस पावन अवसर पर पूज्य सिंधी जनरल पंचायत व भाई बन्ध पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी के नेतृत्व में संयोजकद्वय पुरुषोत्तम शिवानी, नंदू आडवाणी, संरक्षक डॉ. डी.डी. संगतानी, मनोहर नैनवानी, जयकुमार सेवानी, किशन लालवानी, श्री वरूणदेव मन्दिर संचालन समिति के अध्यक्ष प्रमोद ककनानी, पंचायत के महासचिव राजेश चाहूजा, कोषाध्यक्ष प्रितम खैमानी, उपाध्याय दयाराम जैसवानी, सुरेश बाबानी, दिनेश कल्याणी आदि ने सन्त श्री शम्भूलालजी जी का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अन्त में सुख-शांति समृद्धि और आशाओं व मनोकामनाओं की पूर्ण का पल्लव (अरदास) पाकर समाप्ति उपरांत गुरु प्रसादी भण्डारा, निराश्रित बालगृह अपना घर की कन्याओ को खिलाकर संगत ने प्रारम्भ किया। आभार प्रदर्शन दादी पुष्पा पमनानी एवं चन्दा मुलचंदानी ने प्रकट किया।

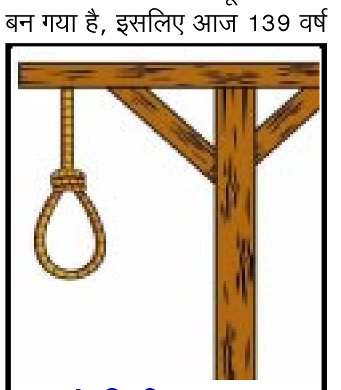

फांसी हो हर हाल

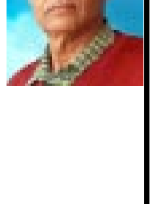

कानून की कमजोरी
फैसलों को मोढ़ेंगे
यूं ही बलात्कारियों
के हौसले बढ़ेंगे।
8 साल की मासूम
वयस्क थे हैवान
अपराध था जघन्य
क्यों बदला विधान।
मंदसौर में उबाल
न्याय का सवाल
उम्र कैद नहीं
फांसी हो हर हाल।

नंदकिशोर राठौर, मंदसौर

******* सफलता की कहानी-उद्योग एवं रोजगार वर्ष-2025 *******

प्रदेश सरकार की उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीतियों से प्रेरित युवा उद्यमी हातिम नजमी ने एएसी ब्लॉक उद्योग से लिखी नई गाथा

नीमच, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। अक्सर युवा उच्च शिक्षा के बाद एक सुरक्षित और मोटी तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन नीमच के एक युवा ने लीक से हटकर अपनी राह बनाई है। नीमच के विदेश से कानून की पढ़ाई कर चुके लॉ ग्रेजुएट श्री हातिम नजमी ने मुख्यनमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा लागू की गई औद्योगिक सरकारी उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीतियों से प्रेरणा लेते हुए, मात्र 22 साल की उम्र में एक बड़ी मासिक आय (10 लाख रुपये) वाली नौकरी का प्रस्ताव ठुकराकर, अपने गृह नगर नीमच में ही उद्योग स्थापित करने का साहसिक निर्णय लिया। इस निर्णय ने, न केवल उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया है, बल्कि 100 से अधिक स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मिला हैं।

बाबजी ए.ए.सी. प्लांट: मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा निर्माण उद्योग-हातिम नजमी के उद्यम, बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण उद्योग ने महज छह माह की अल्प् अवधि में ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा, नीमच में लगभग 3 लाख वर्गफीट क्षेत्र में फैला यह प्लांट 60 करोड़ की लागत से संचालित हो रहा है। आज यह न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण उद्योग है, बल्कि देश के सबसे अत्याधुनिक और नवीनतम तकनीक से लैस ए.ए.सी. ब्लॉक निर्माण संयंत्रों में से एक भी है।

गुणवत्ता और किफायत का प्रतीक: बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक-बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक अपनी बेजोड़ गुणवत्ता और किफायती विशेषताओं के लिए तेजी से पहचान बना रहे हैं। ये ब्लॉक भारतीय मानक ब्यूरो के सख्त गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ ब्यूरो द्वारा तय 4 एम.पी.ए. से भी ज्यादा 5 एम.पी.ए. है। यह उच्च गुणवत्ता इन ब्लॉकों को मजबूत और टिकाऊबनाती है। इन ब्लॉकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये निर्माण लागत में 40 प्रतिशत तक की बचत कराते हैं। कम लागत के साथ-साथ, ये ब्लॉक मजबूत और त्वरित कंस्ट्रक्शन में भी बेहद उपयोगी हैं। ध्वनि और अग्नि प्रतिरोधी (साउंड एवं फायर प्रूफ) होने के कारण, ये आधुनिक निर्माण की जरूरतों को पूरा करते हैं।

दूर-दूर तक फैली पहचान: निर्माण उद्योग में बढ़ती मांग-नीमच में बने बाबजी के ए.ए.सी. ब्लॉकों की मांग अब केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इनका उपयोग कर रही हैं। भोपाल से बीकानेर और दिल्ली से मुंबई तक फैले निर्माण कार्यों में ईन ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारी निर्माण कार्यों र्में भीं इन उच्च गुणवत्ता वाले ए.ए.सी. ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जा रही है। हातिम नजमी की यह सफलता की कहानी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, कि कैसे दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत और सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। बाबजी ए.ए.सी. ब्लॉक आज नीमच की पहचान बन रहे हैं, जो इस युवा उद्यमी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है।

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	69	1851	2130
उडद	20	3600	4699
सोयाबीन	6805	3400	4350
गैहु	6157	2500	2800
चना	417	4906	5422
मसुर	125	5900	6431
धनिया	200	5003	6920
लहसुन	13000	2850	8700
मैथी	624	3402	5200
मुंगफली	903	3500	5152
अलसी	815	6800	7120
सरसो	177	6500	6712
तारामीरा	1	4800	4800
इसबगोल	46	7777	11000
प्याज	2910	251	1174
कलोंजी	96	17501	20681
तुलसी बीज	4	11500	14741
डॉलर	21	5201	7404
तिल्ली	301	6400	8390
जौ	22	2100	2250
मटरसुखी	1	2700	2700
असालीया	72	6250	6791
मूंग	4	6001	6001

स्मार्ट मीटर लगवाएं और 20 प्रतिशत सस्ती बिजली पाएं-मुख्यमंत्री

बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए साल भर चलाएं मेन्टेनेंस गतिविधियां, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा की

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली सबकी जरूरत है। सबको जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं इससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उपभोक्ता को खुद की खपत का आंकलन कर ऊर्जा का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर अपने बिजली बिल की राशि को कम से कम करने की सुविधा भी मिलती है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने की गति को और तेज करने के निर्देश दिये। बताया गया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 21 लाख से भी अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मई-जून में विभिन्न स्थानों पर हुए विद्युत अवरोधों पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए साल भर मेंटीनेंस गतिविधियां चलाई जाएं, ताकि आंधी, पानी या अन्य किसी घटना के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कहा कि मेंटीनेंस गतिविधियों में नई एप्रोच के साथ नए उपाय किए जाएं। नये उपकरण क्रय किये जाएं। जहां घने पेड़ हैं, उनके नीचे से गुजरने वाले बिजली के तारों में कोटिंग कराएं। पॉवर/लाइन लॉसेस कम से कम करें और ऊर्जा की बचत के सभी तरीकों पर गंभीरता से अमल करें।

विद्युत उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करें- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घरेलू हो या औद्योगिक सभी जगह विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को सोलर पॉवर के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली स्वयं पैदा कर अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विद्युत उपयोग को भी सोलर पॉवर से चलित पम्पों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जरूरत वाले जिलों में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभागीय नीति तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियों को सर्वाधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिलकर प्रयास करें।

बिजली कंपनियों को दो वर्ष में लाएं लाभ की स्थिति में- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले दो साल में तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लाभ की स्थिति में आ जाएं इसके लिए विद्युत कंपनियां अपनी आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करें। नई तकनीक इस्तेमाल करें, नवाचार करें, ताकि कंपनी के साथ-साथ उपभोक्ताओं को फायदा मिले।

रबी सीजन में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी 2025-26 के लिये पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके लिये अभी से तैयारियां शुरू करें। बैठक में बताया गया कि रबी सीजन में लगभग 20200 मेगावॉट विद्युत मांग संभावित है। गत वर्ष यह मांग 18 हजार 913 मेगावॉट थी।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम- ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है। घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी मूल बिजली बिल राशि में अधिभार की छूट देकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी गई है। यह स्कीम छह माह की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस अवधि के बाद भी बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तओं का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों के नये सेटअप के संबंध में भी चर्चा की। श्री तोमर ने मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृति पर उनका आभार व्यक्त किया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मंडलोई ने बताया कि दूसरे राज्यों की तुलना में ऊर्जा के प्रमुख सूचकांकों में (संग्रहण दक्षता में) मध्यप्रदेश देश में पहले नम्बर पर है। प्रदेश में 97.92 प्रतिशत संग्रहण क्षमता हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ अगले तीन वर्षों के लिए अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 तक ऊर्जा विभाग बिजली दर टैरिफ में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान विभाग बिल दक्षता 90 प्रतिशत, संग्रहण दक्षता 99 प्रतिशत और एटी एण्ड सी हानि को 14 प्रतिशत तक कम कर लेने के लक्ष्य के लिए प्रयासरत है।

पीएम जन-मन में शत प्रतिशत परिवारों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य- बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के 29 हजार 290 परिवारों के घरों को शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर देने का लक्ष्य लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 21 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों के घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 55 हजार 795 परिवारों के घरों को भी शतप्रतिशत विद्युतिकृत करने की विभाग की योजना है। यह लक्ष्य इसी वित्त वर्ष में प्राप्त लिया जाएगा।

प्रदेश के छह महानगरों में खोले जाएंगे एक-एक विद्युत पुलिस थाने- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा पुलिस संरचना स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के छह महानगरों में एक-एक (कुल छह) विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में यह पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग दस्तों को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। औचक निरीक्षण करेंगे और केस डायरी भी तैयार करेंगे। विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ताकि डिस्कॉम की सम्पत्ति की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए बकाया वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में विद्युत के उपयोग का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा इसके लिए वितरण कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है।

शासकीय कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड मीटर- बैठक में बताया गया कि शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त से प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा। इससे शासकीय कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या नहीं होगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, प्रबंध संचालक मप्र ऊर्जा विकास निगम, तीनों विद्युत वितरण कंपनी लि. के सीएमडी तथा अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शराब की हर बोतल का हिसाब रखेगा आबकारी विभाग, पीओएस मशीन से होगी बिलिंग

भोपाल, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश की शराब दुकानों पर बिक्री के लिए आई शराब की हर बोतल का हिसाब अब आबकारी विभाग के पास होगा। समस्त शराब दुकानों पर पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन से ही शराब विक्रय की बिलिंग की जाएगी। दुकान स्तर तक शराब के ट्रैक एंड ट्रेस को लागू किया जाएगा। इससे शराब की हर बोतल आबकारी विभाग के सर्वर से जुड़ जाएगी।

हर बोतल का हिसाब-किताब...

इस प्रक्रिया से विभाग के पास सभी दुकानों की रोजाना की यह जानकारी होगी कि किस दुकान से किस ब्रांड और किस बैच की शराब किस कीमत पर बेची गई। यानी अब विभाग के पास हर बोतल का हिसाब-किताब होगा। पीओएस मशीन के जरिए शराब बेचने का मसौदा तैयार किया है। पीओएस मशीन की खरीदी के लिए जल्द ही बिड जारी को जाएगी। इसके बाद प्रदेश की सभी 3 हजार 553 शराब दुकानों पर पीओएस के जरिए ही शराब बिकेगी।

बगैर पीओएस के ही बेची जा रही शराब...

मौजूदा शराब नीति में पीओएस मशीन से शराब बेचने का प्रविधान है, लेकिन तीन माह से बगैर पीओएस के ही शराब बेची जा रही है। भोपाल सहित प्रदेशभर की अधिकांश शराब दुकानों में महंगे दामों में शराब बेचने के प्रकरण सामने आए हैं।

गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए उठाया कदम...

कुछ जिलों में कलेक्टर के निर्देश पर शराब दुकानों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐसे में शराब दुकानों से महंगी शराब बेचने या अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने यह कदम उठाया है। इस व्यवस्था के लागू होने से शराब ठेकेदार एमआरपी से ज्यादा या कम में शराब नहीं बेच सकेगा।

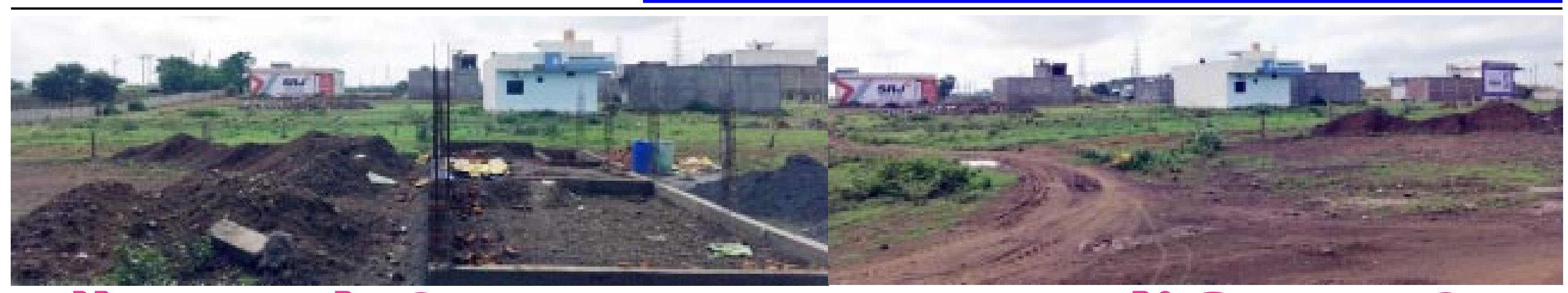

अवैध कालोनी का मामला न्यायालय में विचाराधीन, रजिस्ट्रियां रुकवाना चाहिए थी, कर रहे नामांतरण

पिता के नाम पर दर्ज हुआ प्रकरण तो पुत्र को पावर देकर बेचने लगे अवैध कॉलोनी में भूखंड

सुवासरा, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। नगर सहित क्षेत्र मे इन दिनों सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त चरम पर है। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर खुले रूप से अवैध कॉलोनियों में भूखंड बेच रहे है। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जो कि प्रशासन की सांठगांठ से ये सारा खेल होना दर्शा रहा है। रुणिजा रोड स्थित एक ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी का मामला सामने आया हैं। इस कॉलोनी की एफआईआर होने के बाद प्रकरण सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद बिना किसी आधार के प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कई छोटे छोटे आवासीय भूखंडो के नामांतरण कर दिए गए।

नायब तहसीलदार ने कराई थी एफआईआर -मामला रुणीजा रोड स्थित भूमि सर्वे नंबर(3/1/1/1/1/1/1/1/1/2) मे 1.10 हेक्टर भूमि का है. कॉलोनाइजर रामप्रसाद बैरवा ने बिना किसी विकास अनुमति अभिमत के अवैध कॉलोनी का निर्माण कर कई प्लॉट विक्रय कर दिए। जब इस अवैध कॉलोनी की शिकायत नगर के जागरूक लोगो द्वारा तहसीलदार को की गयी तो तत्कालीन नायब तहसीलदार ओशिन धन्यवाद ने जांच दल गठित किया. जांच मे पाया गया की कॉलोनाइजर ने बिना किसी सक्षम अधिकारियों की बगैर अनुमति नियम विरुद्ध अवैध कालोनी बनाकर प्लॉट विक्रय कर दिए. जिसके बाद 11मई 2022 को नायब तहसीलदार ने सुवासरा थाने मे स्वयं उपस्थित होकर उक्त कॉलोनाइजर रामप्रसाद बैरवा के विरुद्ध धारा 61(2)(3)(4) के अंतर्गत प्रकरण करवाया था।

लाभ पहुंचाने के लिए लिया लाभ- थाने मे प्रकरण दर्ज होने के बाद वर्ष 2023 और 2024 मे अवैध कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए कस्बा पटवारी और तहसीलदार मोहित सीनम ने तत्कालीन एस डी एम राजेश शाह को पत्र लिखकर अभिमत लेकर अवैध कॉलोनी में विक्रय हुए छोटे-छोटे आवासीय भूखंडों का नामांतरण कर दिया गया। इतना ही नहीं राजस्व विभाग के कुछ पटवारियों ने बारी-बारी से अवैध कॉलोनाइजर से नामांतरण करवाने के बदले में उक्त भूमि पर प्लांट ले लिए और नामांतरण करवा दिए।

पिता पर प्रकरण दर्ज हुआ तो पुत्र को पावर देकर बेच रहे भूखंड- 2022 में जब इस अवैध कॉलोनी को लेकर रामप्रसाद बैरवा पर प्रकरण दर्ज हुआ तो रामप्रसाद ने इस कॉलोनी में भूखंड बेचने का पावर उसके पुत्र अनिल बैरवा को दे दिया। अवैध कॉलोनी वही है। प्रकरण भी उसी कॉलोनी पर दर्ज है। मामला न्यायालय में भी उसकी कॉलोनी का चल रहा है। बस बेचवाल का नाम बदल गया। ओर प्रशासन को चुना अब अलग नाम से लग रहा है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन कॉलोनाइजर को पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है।

रजिस्ट्रियां रुकवाना चाहिए, कर रहे नामांतरण- रुणिजा रोड स्थित रामप्रसाद बैरवा की इस अवैध कॉलोनी का मामला 2022 में हुई एफआईआर के बाद सीतामऊसिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। जिसकी अगली सुनवाई 14 नवंबर 2025 को होना है। इसको लेकर राजस्व विभाग के आला अधिकारियों को इस कॉलोनी के भूखंडों की रजिस्ट्रियां रुकवाना चाहिए थी। लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रियां रुकवाना तो दूर वहां के भूखंडों के नामांतरण धड़ल्ले से किए जा रहे है।

राजस्व अधिकारियों से लेकर सरपंच सचिव तक की संदिग्ध भूमिका- उक्त भूमि ग्राम पंचायत किशोरपुरा के अधीन आती है इसलिए इस पंचायत के सरपंच और सचिव की भूमिका भी संदिग्ध है ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के उनकी सीमा क्षेत्र में इस तरह की निजी जमीनों पर कई अवैध निर्माण हो गए इन्होंने कभी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की. वहीं तहसीलदार मोहित सिनम ने इस अवैध कॉलोनी पर विशेष मेहरबानी दिखाई और तत्कालीन एसडीएम राजेश शाह से अभीमत लेकर ताबडतोड़ नामांतरण कर दिए। फिलहाल तो इस अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज हुआ था वो अभी न्यायालय सीतामऊमें विचारधीन हैं।

इस कॉलोनी को लेकर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। में पता करके दिखवाती हूं।

शिवानी गर्ग, एसडीएम सीतामऊ

ग्राम पंचायत द्वारा इस अवैध कॉलोनी में भवन निर्माण की कोई परमिशन नहीं दी गई है और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

गोपालसिंह झाला, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत किशोरपुरा

कार से आए बदमाशों ने की फायरिंग

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, तीन नाकाबपोशों ने किया हमला

नीमच, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जिले के गांव केरी में बुधवार रात स्कार्पियो से आए नकाबपोश तीन बदमाशों ने दशरथ सिंह तोमर के घर हमला कर दिया। जीरन थाना पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने पहले स्कार्पियो से मकान का लोहे का गेट तोड़ा। इसके बाद घर में घुसकर रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने सबसे पहले मकान की दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया। हालांकि, गोलियां कैमरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। गोलियां दीवारों से टकराई, जिससे दीवारों का प्लास्टर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पूरी वारदात मकान के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। अभी तक हमले का कारण और किसे निशाना बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दशरथ सिंह तोमर ने जीरन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

कलेक्टर ने दो आदतन अपराधी को किया जिलाबदर

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत दो आदतन अपराधी याकूब खाँ पिता बुन्दु खाँ निवासी जयपुरा खिलचीपुरा थाना नई आबादी जिला मंदसौर एवं शेरू पिता खाजू न्यारगर निवासी बोतलगंज थाना पीपल्यामण्डी जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

सावन में ओंकारेश्वर में शिव आराधना का महासंगम

हर दिन होगा 2,51,000 बार ॐ नमः शिवाय जाप

ओंकारेश्वर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। पवित्र सावन माह की शुरुआत इस वर्ष 4 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही संपूर्ण भारत में भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व आरंभ हो जाएगा। इसी कड़ी में मां नर्मदा के तट पर स्थित खेड़ी घाट (मोरटक्का) स्थित महर्षि वाल्मीकि धाम आश्रम में सावन को आध्यात्मिक भक्ति और मंत्रोच्चार से भरे भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाएगा।

आश्रम के संस्थापक लखन सिंह तंवर ने जानकारी दी कि पूरे एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन विद्वान आचार्यों द्वारा 2,51,000 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जाएगा। यह आयोजन न केवल शिव उपासना को समर्पित होगा, बल्कि समाज में धार्मिक चेतना और जागरूकता भी फैलाएगा।

आयोजन की प्रमुख विशेषताएं, रोजाना 25,000 रुद्राक्षों का अभिमंत्रण- ✻ पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन ✻ हर सोमवार विशेष रुद्राभिषेक ✻ 12 ज्योतिर्लिंगों पर मां नर्मदा जल से महाअभिषेक

प्रत्येक दिन जल कलश पूजन एवं मंत्रों द्वारा पूजन अनुष्ठान- इस आयोजन में देशभर से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि धाम आश्रम में होने वाले इस भक्ति महोत्सव को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आश्रम परिवार का मानना है कि यह आयोजन न केवल शिव आराधना का केंद्र बनेगा, बल्कि यह लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देगा। सावन मास के दौरान ओंकारेश्वर और आसपास के क्षेत्र में कई मंदिरों और तीर्थस्थलों पर महाआरती, हवन, भंडारे और विशेष पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और बड़ी संख्या में शिव भक्त, साधक और तांत्रिकों को एकत्र करता है। श्रद्धालुओं के लिए आयोजन स्थल पर भोजन, रुकने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और जलपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी इस धार्मिक आयोजन की सफलता हेतु सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है।

शासकीय/अशासकीय स्कूलों में बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर चस्पा करें-डा.शर्मा

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने बैठक कर निर्देश दिए

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ निवेदिता शर्मा, सदस्य श्री ओंकार सिंह ने जिला पंचायत में बैठक कर जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए किशासकीय/अशासकीय स्कूलों में बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर चस्पा करें। स्कूलों, छात्रावासों में शिकायत पेटी भी लगवाए। शिकायत के निराकरण के लिए समिति बनाएं तथा समय पर शिकायत का निराकरण करें। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समिति बनाएं तथा जितने प्रकरण है उनका तुरंत निराकरण करें। बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की काउंसलिंग के लिए अलग से रूम हो। बच्चों के संबंध में सपोर्ट पर्सन से बात करें। सपोर्ट पर्सन से लगातार संपर्क में रहे। वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहे। जेजे एक्ट को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें। प्रकरणों में पुलिस अपनी पूरी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से करें। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री बीएल वैष्णव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।

बच्चों की शिक्षा के अधिकारों का हनन न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। श्रम विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम न हो इसके लिए लगातार निरीक्षण करें, चेकिंग करें। ऐसे श्रमिक जिनको न्यूनतम से कम वेतन मिल रहा है उनको वेतन दिलाए। महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह रोकने के लिए एक टीम बनाएं। इसके लिए एसओपी निर्धारित करें। बाल विवाह रोकने के बाद उसका फॉलोअप भी लेवे। बाल विवाह न हो इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। घुमंतु समुदाय के बच्चों को छात्रावास की सुविधा दिलाए, इसके लिए प्रयास करें। ऐसे बचे छात्रावास में अधिक से अधिक जाए इस हेतु बच्चों को प्रेरित करें। ऐसे बचे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ने के कारण को समझे और उसका समाधान निकालें। जिले में कोई मदरसा बिना पंजीयन के नहीं चले इसका निरीक्षण करें तथा समय-समय पर जांच करें। मदरसों की मान्यताओं को चेक करें।

प्रदेश में अवैध कालोनाइजर्स पर टेक्नीकल स्ट्राइक, रजिस्ट्री के समय सॉफ्टवेयर मांगने लगा परमिशन

भोपाल, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर अवैध कॉलोनाइजरों के लिए तकनीकी स्ट्राइक साबित हो रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है, वहीं भूमाफिया पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम कमियों के चलते हो नहीं पा रही हैं। संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर में खसरा नंबर दर्ज करते ही प्रापर्टी की पूरी जानकारी ऑनलाइन दिखने लगती है। इससे पता चल जाता है कि यह प्रापर्टी किसकी है, कहां है और किसके द्वारा बेची गई है। साथ ही उसके बेचने वाले कॉलोनाइजर ने अनुमतियां ली हैं या अवैध रूप से प्रापर्टी बेची गई है, इसका भी पता चल जाता है।

आज मंदसौर बंद की अपील, ज्ञापन देंगे

मासूम के मुजरिमों को फांसी देने की मांग

मंदसौर, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को मंदसौर बंद की अपील वायरल हुई। जिसमें मंदसौर की समस्त जनता के नाम से नगर बंद रखने की बात कही गई है। मामला है मासूम बच्ची के साथ कुछ साल पहले हुये दुष्कृत्य का। जिसमें आरोपियों की फांसी की सजा के फैसले को बदलते हुए सेशन न्यायालय ने आजीवन जैल में रहने का फैसला दिया है। बंद की अपील में कहां गया है कि दोपहर 3.00 बजे सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। जिसमें आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की जाएगी। सुबह 10.00 बजे गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय पर सभी एकत्रित होकर बंद को सफल बनाने की अपील के लिए रवाना होंगे। दिन भर लोग शहर में दुकाने बंद कराते रहेंगे।

नपा सभागृह में बैठक में शामिल सर्वसमाजजन

जमीन पर कब्जा करने के लिए गुंडे, बदमाशों को भेजने का आरोप..!

पिपलियामंडी, 03 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। बायपास मार्ग पर जमीन विवाद में गुंडे, बदमाशों को भेजकर कब्जा हटाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए युवक ने पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराई। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है जमीन मेरी है, मैं खाली करवाने के लिए किसी को भेज सकता हूं। पिपलियामंडी बायपास मार्ग पर निवासरत ललित शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा ने पिपलिया चौकी पर शिकायत दर्ज कराई कि सुनिल पिता मांगीलाल निवासी जमनावदा तह, छोटीसादडी (राज.) ने मेरे कब्जे की जमीन को खाली कराने के लिए 15 से 20 गुंडे, बदमाश भेजे। जबकि जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। समझौते बतौर सुनील ने 53 लाख रुपए देने की लिखपढ़ी कराई थी, लेकिन रुपए नही दिए और करीब 15 गुंडे, बदमाशों को भेजकर मेरे व मेरी माताजी के साथ मारपीट करवाई गई। जमीन पर मेरी माताजी के नाम से लगा बोर्ड भी हटा दिया। जबकि उक्त भूमि को लेकर न्यायालय मे प्रकरण चल रहा है। इधर सुनील पिता मांगीलाल का कहना है कि कोर्ट से मेरे पक्ष में फैसला हुआ है, जमीन मेरी है, दूसरे को इस पर रहने का अधिकार नही है। मैं कब्जा करने के लिए किसी को भी भेज सकता हूं। चौकी प्रभारी धर्मेश यादव का कहना है चचेरे भाईयों के बीच जमीन विवाद का मामला है, दोनों ने आवेदन दिए है। मारपीट जैसी कोई बात सामने नही आई है।

कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर (मप्र)

क्रमांक/ मंदसौर दिनांक

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वाहन स्वामी बंशीलाल राठौर पिता धन्नालाल निवासी ग्राम बिल्लोद, जिला- मंदसौर की मृत्यु दिनांक 10-08-2023 को हो गई है। इनके ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 14 एसी 5347 को इनकी पत्नी श्रीमती टमाबाई पति बंशीलाल ने अपने नाम पर अंतर्गण दर्ज कराने हेतु इस कार्यालय में मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

इस प्रकाशन अवधि के सात दिवस में यदि किसी को आपत्ति हो तो इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके पश्चात वाहन श्रीमती टमाबाई के नाम अंतरण कर दिया जावेगा।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंदसौर

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक– आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 313880, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in